



अधिकतम : 32°C
न्यूनतम : 18°C

सबसे छुपाता नहीं, छपता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, गुरुवार 16 अप्रैल 2026 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 229 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

वैसाख कृष्ण पक्ष 14 विक्रमी संवत् 2083

27 श्याल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुगदाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



महिला आरक्षण में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित हो: मायावती



धीमी ओवर गति के लिए अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा



सही समय: महिला आरक्षण से बदलेगी भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर



इजरायल-लेबनान ने तीन दशक बाद की सीधी बातचीत

CBSE: 10वीं के नतीजों में बेटियां अक्ल

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस वर्ष देशभर के 22 रीजन में घोषित किए गए हाईस्कूल परीक्षाओं में कुल 93.70 फीसदी छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं। इस बार भी परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है और बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी बहत कायम रखी है। इस साल त्रिवेन्द्रम रीजन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.79 फीसदी के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। नोएडा रीजन का प्रदर्शन इस बार गिरा है। यहाँ पास प्रतिशत 87.66 फीसदी रहा, जो पिछले साल के 90.75 फीसदी के मुकाबले 3.09 फीसदी कम है। इससे साथ ही परीक्षा देने वाले 25 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। बुधवार शाम 4 बजे उमंग और डिजिटलकर सहित सभी सरकारी पोर्टल



सक्रिय हो गए और फ्लैश संदेश के जरिये परीक्षाओं की घोषणा की गई। सीबीएसई की नई डि-बोर्ड प्रणाली के तहत, इस बार कक्षा 10वीं के नतीजें

93.70 प्रतिशत छात्र हुए पास, लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99 व लड़कों का 92.69% रहा

प्रणाली के तहत शैक्षणिक वर्ष को दो अलग-अलग परीक्षा सत्रों में विभाजित किया गया है। पहला सत्र, जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था, 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 के बीच आयोजित किया गया था। यह परीक्षाएं देश भर के 8,075 परीक्षा केंद्रों पर 83 विषयों के लिए आयोजित की गईं। इस वर्ष कुल 25,08,319 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल थीं। बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा चरण 15 मई से शुरू होने वाला है। छात्र अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी मार्कशीट और प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब: ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक संभावित कूटनीतिक सफलता का भी दिया संकेत

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को घोषणा की कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त होने के करीब है। उन्होंने एक संभावित कूटनीतिक सफलता का संकेत भी दिया है। ट्रम्प ने संकेत दिया कि रुकी हुई बातचीत पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में फिर से शुरू हो सकती है, जिससे युद्धविराम समाप्त होने से पहले किसी समझौते की उम्मीद जगी है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ काफ़ी सख्त कर दी है। सेना ने पुष्टि की है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से घेराबंदी लागू करते हुए ईरानी समुद्री व्यापार को प्रभावित करने में कामयाब रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के प्रमुख ब्रेड कूपर ने कहा कि इस अभियान ने 36 घंटों से भी कम समय में ईरान की व्यापारिक जीवन रेखा को पंगु बना दिया है। ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी पूरी तरह से

खोलने की भी मांग कर रहा है। दोनों पक्षों द्वारा समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के कारण 10 अप्रैल को हुई पहले दौर की बातचीत के बाद मुख्य मुद्दे अनुसूद्धे रह गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडो वेंस ने दोनों पक्षों के बीच तब तक बातचीत का आसपास है, लेकिन हालात सामान्य होते ही इसमें तेज गिरावट आएगी।

लार्ग कर दी गई है। ईरान की लगभग 90 प्रतिशत अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है, जो अब प्रभावित रूप से ठप हो गई है। शक्ति प्रदर्शन के बावजूद मुख्य गतिरोध अभी भी बने हुए हैं। अमेरिका ईरान के यूरैनियम संवर्धन को तत्काल रोकने और प्रमुख परमाणु केंद्रों को नष्ट करने की मांग कर रहा है। साथ ही होर्मुज को फिर से

संक्षिप्त समाचार

चीनी टैंकर होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम
तेल अवीव/तेहरान। अमेरिकी प्रतिबंध खोल रहा चीनी टैंकर रिच स्टैरी बुधवार को फिर से होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी नहीं तोड़ पाया। यह टैंकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के हमरियाह पोर्ट से चला था। वहाँ से इसमें करीब 2.5 लाख बैरल मेशेनला लोड किया था। यह टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होर्मुज के आगे अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी इस टैंकर ने मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की थी।

राधव चड्ढा को केंद्र ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद राधव चड्ढा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सूत्रों के अनुसार खुफिया ब्यूरो (आईबी) को खतरे की आशंका को लेकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर राधव चड्ढा को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पंजाब सरकार द्वारा राधव चड्ढा को दी गई जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला आप नेता के संसद में पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में कथित विफलता के चलते उठाना गया है।

पश्चिम एशिया संसदीय उद्घाटन में 7.9 फीसदी गिरावट
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अप्रैल महीने की हवाई यात्रा पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन में व्यवधान देखने को मिला। जबकि वैश्विक व्यापार भी इससे प्रभावित हुआ है, जिससे कई देशों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। ओएजी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल महीने में देश की कुल विमानन क्षमता जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटनों की क्षमता में आई तेज कमी है, जो लगभग 7.9 प्रतिशत तक पहुंच गई।

सम्राट ने ली सीएम पद की शपथ बिहार में मंत्रियों की सूची से पहले बंटे विभाग

पटना, वार्ता

भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही विभागों के प्रारंभिक बंटवारे की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह, सामान्य प्रशासन, नगर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पथ निर्माण समेत कुल 29 विभाग अपने पास रखे, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड को मात्र 18 विभाग दिए गए। गृह विभाग सहित मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू तत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी मत्स्य एवं पशु



मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह समेत 29 विभाग रखे। दोनों उप मुख्यमंत्री को मिलाकर जयदयू को मात्र 18 विभाग दिए गए।

पवन खेड़ा को सुप्रीम झटका शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत पर लगाई रोक

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक हफ्ते की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला असम में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अदालत एस. चंद्रकर की पीठ ने इस मामले में खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह नोटिस असम सरकार को उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल संबंधित आदेश (ट्रांजिट बेल) पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर खेड़ा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि कथित अपराध और एफआईआर दोनों असम में दर्ज हैं। उन्होंने इसे फॉर्म चुनने की कोशिश बताते हुए कानून का दुरुपयोग करार दिया। असम सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें खेड़ा को एक सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट ने यह राहत इसलिए दी थी, ताकि खेड़ा संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। तेलंगाना हाईकोर्ट की एकल पीठ, जस्टिस के सुजाता ने आदेश दिया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में खेड़ा को एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत पर रखा गया। खेड़ा ने यह राहत तब मांगी थी, जब असम पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।



असम के सीएम की पत्नी पर लगाए थे कई पासपोर्ट रखने के आरोप से जुड़ा मामला

समुद्र में गुंडागर्दी बर्दाशत नहीं की जाएगी: जयशंकर

नई दिल्ली/ टोक्यो। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का डंडा बजाया है। जापान की ओर से आयोजित एशिया जीरो एमिशन कन्फ्रेंस में आभासी बैठक में जयशंकर ने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमले किसी भी कोमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। इस बैठक का

अयाप्पा मंदिर रेस्टोरेट नहीं: सबरीमाला मैनेजमेंट

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने कहा कि यह खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यह आजन्म ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता का मंदिर है। टीडीवी का पक्ष रखते हुए एडवोकेट अधिपंक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 से 50 साल के उम्र की महिलाएं देवता के

कहा: यहाँ ब्रह्मचारी देवता, महिलाएं क्यों आना चाहती हैं

स्वरूप और पहचान के विपरीत हैं। भारत में अयाप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहाँ जाएं। उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे

LPG लेकर गुजरात के बंदरगाह पहुंचा 'जग विक्रम'

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला जहाज जग विक्रम करीब 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी पर पहुंच गया है। पोर्ट अथॉरिटी के अनुसार यह जहाज दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में मंगलवार रात ऑयल जेट्टी-1 पर सुरक्षित रूप से लंगर डाल चुका है। अधिकारियों ने बताया कि यह



टैंकर 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर आगे बढ़ा था। यह हाल के दिनों में क्षेत्र में घोषित दो सप्ताह के युद्धविराम के बाद इस मार्ग से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह जहाज मार्च की शुरुआत के बाद फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है।

हाल के दिनों में क्षेत्र में घोषित दो सप्ताह के युद्धविराम के बाद होर्मुज मार्ग से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज

समुद्र यूरैनियम से जुड़े विवाद को सुलझाने में सहयोग देने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को बीजिंग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मास्को इस समस्या के समाधान में विभिन्न तरीकों से योगदान दे सकता है। इसमें उच्च स्तर पर संबंधित यूरैनियम को ईंधन-ग्रेड यूरैनियम में बदलना या उसका एक हिस्सा रूस में सुरक्षित रखना जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। लावरोव ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी कदम ईरान की सहमति से और उसके अधिकारों का सम्मान करते हुए ही उठाना जाएगा।

विपक्ष करेगा महिला आरक्षण बिल का विरोध

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लागू करने की योजना बना रही है, वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और जनता को गुमराह करने वाला कदम है।

खड्गे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा कि हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लेकर आई है, वह राजनीति से प्रेरित है। हमने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन हमारा आग्रह है कि पुराने संशोधनों को लागू किया जाए। सरकार परिसीमन और जनगणना के नाम पर चालें चल रही हैं। कार्यपालिका के जरिये संविधान की उन शक्तियों को हथियारा रही है, जो संसद और संस्थाओं के

खड्गे बोले: नीयत में खोट है, यह सिर्फ चुनावी पैराना

पास होनी चाहिए, इन्होंने पहले भी असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन में हमें धोखा दिया है। इसलिए हम इस बिल के मौजूदा स्वरूप का एकजुट होकर संसद में विरोध करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन हम इस बिल के साथ जोड़ी गई परिसीमन की प्रक्रिया के पूरी तरह खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की शर्तों में उलझाना सरकार की एक सोची-समझी चाल है, जिससे इस अधिकार को लंबे समय तक टाला जा सके, इसलिए विपक्ष महिलाओं को हक देने का तो पक्षधर है लेकिन सरकार के इस तरीके का पुरजोर विरोध करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के यहाँ स्थित आवास पर विपक्ष के जरिये बिल नेताओं ने बैठक में भाग लिया।

संक्षिप्त समाचार

प्लास्टिक अपशिष्ट गोदाम में आग लगने से तीन लोगों की मौत नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के बुध विहार इलाके में प्लास्टिक अपशिष्ट गोदाम में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित एक ऐसे परिवार के सदस्य थे जो बुध विहार के मांगे राम पार्क इलाके में स्थित गोदाम में बनी एक अस्थाई झोपड़ी में रहते थे। यह घटना मध्यरात्रि के दौरान घटी जब साइट पर रखे अपशिष्ट में आग लग गई और वह तेजी से झुगगी में पकल गई। दमकल कर्मियों की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशकत के बाद बुधवार सुबह आग पर काबू पालिया गया। शव बुरी तरह जले हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

अनंत स्वरूप बने फिक्की के नए महासचिव नई दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की ने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) के पूर्व अधिकारी अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति बुधवार 15 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। फिक्की ने मीडिया को दी जानकारी में कहा है कि 1992 बैच के आईआरपीएस अधिकारी स्वरूप की नियुक्ति देश के उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर सांठन के वरिष्ठ नेतृत्व को और सशक्त बनाती है। उनके पास लोक नीति, लॉजिस्टिक्स, विनियामक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का तीन दशक से भी अधिक का अनुभव है।

महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र लागू किया जाए: मायावती

महिला आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित किया जाए

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33 प्रतिशत आरक्षण में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, तो इस कदम का वास्तविक उद्देश्य काफ़ी हद तक निष्पत्ती हो जाएगा।



सुश्री मायावती ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की पहल उचित और स्वागतयोग्य है, भले ही इसमें देरी हुई हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार हाशिए पर रही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान किया जाना ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम होगा। उन्होंने कहा कि केवल सामान्य महिला आरक्षण से इन वर्गों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब संसद में महिला आरक्षण लागू करने को लेकर बुलाने के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, तो इस कदम का वास्तविक उद्देश्य काफ़ी हद तक निष्पत्ती हो जाएगा।

लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को लागू करने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने से महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन पर 16 अप्रैल को चर्चा प्रस्तावित है, साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल पर भी विचार किया जाएगा। सरकार 2029 के आम चुनाव से लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण

नोएडा में श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो

अचानक भड़की हड़तालों और हिंसक घटनाओं ने प्रशासन को भी चौंका दिया

नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के उग्र विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार सतक हो गई है। श्रम मंत्रालय के तहत मुख्य श्रम आयुक्त ने हालात को विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अधिकांशों के अनुसार अचानक भड़की हड़तालों और हिंसक घटनाओं ने प्रशासन को भी चौंका दिया है। दरअसल विरोध की शुरुआत सात अप्रैल को हरियाणा के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र से हुई, जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य-शिफ्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मंगलवार को नोएडा के सेक्टर-62 में भी श्रमिकों का गुस्सा पकूट पड़ा, जहां बड़ी संख्या में मध्यम उद्योग स्थित हैं और स्थिति हिंसक हो गई। केंद्र

सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बात को भी जांच कर रही है कि कहीं श्रम संहिताओं को लेकर गलत जानकारी पकड़कर श्रमिकों को भड़काया तो नहीं जा रहा। हालांकि इस पर श्रम मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। श्रमिकों का आरोप है कि महंगाई तेजी से बढ़ी है, खासकर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते, लेकिन उनके वेतन में उसके अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। नई श्रम संहिताओं के बाद वेतन संरचना में बदलाव से भी उनकी आय पर असर पड़ा है, जो बढ़ते खर्चों के सामने अपर्याप्त साबित हो रही है। भारतीय ट्रेड यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा कि वेतन और शिफ्ट जैसे मुद्दे प्रमुख हैं और इस समय सरकार के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई अश्रिमक नेताओं को नजरबंद कर रखा है। नोएडा में यूनियन के जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा को भी नजरबंद किए जाने की बात सामने आई थी। प्रशासन ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता शुरू कर दी है। उद्योगपतियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने से उत्पादन पर असर पड़ा है, जिससे वेतन बढ़ाना उनके लिए नीतीतिपूर्ण हो गया है। विवाद की जड़ न्यूनतम वेतन में नियमित संशोधन को लेकर बताई जा रही है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होता है और आमतौर पर साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है।

शाहतूश कारोबारी वन्यजीव अपराध में दोषी करार

नई दिल्ली, वार्ता

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने लुप्तप्राय तिब्बती मृग चिरु के बालों से बने शाहतूश शॉल के अवैध निर्यात के आरोप में जयपुर स्थित मेसर्स इंडियन आर्ट गैलरी के मालिक सैयद शाहिद अहमद काशानी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोषी करार दिया है।

1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है और कानूनी रूप से इसका व्यापार प्रतिबंधित है। पिछले 51 साल से शाहतूश शॉल के व्यापार पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध है। एक सरकारी विज्ञापन के अनुसार इस मामले की अनुठी विशेषता वन्यजीव अपराध निबंधन ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), सीमा शुल्क और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के बीच लगभग 17 वर्षों तक चले निरंतर समन्वय का परिणाम बताया जा रहा है। डब्ल्यूसीसीबी को यहाँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्यात खेप में 1,290 शाहतूश शॉल होने का पता चला और पकड़वरी 2009 में सीबीआई और शिकायत दर्ज की गई। यह पहली बार था, जब वन्यजीव अपराध के मामले में सीबीआई के माध्यम से मुकदमा चलाया गया।

प्रधानमंत्री ने परिसीमन मुद्दे पर राष्ट्र के साथ जानबूझकर छल किया

कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर मोदी पर बोला हमला

नई दिल्ली, वार्ता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लीखा हमला बोला और सरकार पर जानबूझकर धोखा देने और संसदीय प्रतिनिधित्व पर पहले दिए गए आश्वासनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखे एक तीखे पोस्ट में, रमेश ने आरोप लगाया कि परिसीमन पर प्रधानमंत्री के दावों का आगामी संसद के विशेष सत्र के लिए प्रसारित विधेयकों में खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक तथाकथित नेता हैं, जिनकी एकमात्र विशिष्ट विशेषता उनकी बेजोड़ भ्रामक नेतृत्व क्षमता है। उन्होंने परिसीमन मुद्दे पर राष्ट्र के साथ जानबूझकर छल किया है।



संसदीय प्रतिनिधित्व पर पहले दिए गए आश्वासनों को कमजोर करने का आरोप लगाया

महिला आरक्षण चर्चा का नहीं, तत्काल क्रियान्वयन का मामला है: डा. अनिल

नई दिल्ली। कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन डा. अनिल जय हिंद ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण चर्चा का नहीं, बल्कि उसके तत्काल क्रियान्वयन का मामला है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें संविधान संशोधन लाने की तैयारी है। जय हिंद के अनुसार पहले सरकार ने 2027 में जातिगत जनगणना, उसके बाद परिसीमन और फिर महिला आरक्षण लागू करने का रोडमैप बनाया था, लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करने की बात कही जा रही है, जो मौजूदा जनसंख्या बदलावों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जातिगत जनगणना से बचना चाहती है। इस संदर्भ में 2021 में संसद दिए गए आश्वासन और उच्चतम न्यायालय में दिए गए हलफनामों का हवाला दिया गया।

दोने का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि वह सत्ता हथियाने की अपनी अशिष्ट प्रवृत्ति से ऊपर उठकर एक राजनेता बनने में असमर्थ हैं यहाँ तक कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी।

सेंसेक्स 78111.24 निपटी 24231.30 सोना 15299 चांदी रु. 239934

शेयर बाजारों में लौटी तेजी सेंसेक्स 1264 अंक चढ़ा

मुंबई, वार्ता

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पिफर शुरू होने की उम्मीद में घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी लौट आई और बीएसई का सेंसेक्स 1,263.67 अंक (1.64 प्रतिशत) चढ़कर 78,111.24 अंक पर बंद हुआ।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटी-50 सूचकांक भी 388.65 अंक यानी 1.63 प्रतिशत की बढ़त में 24,231.30 अंक पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान में शांति वार्ता दो दिन में पिफर शुरू हो सकती है। इससे निवेशकों में उत्साह देखा गया। उत्साहित निवेशकों की लिवाली से सभी सूचकांकों और सभी सेक्टरों में तेजी रही। मझौली कंपनियों का निपटी मिडकैप-50 सूचकांक 2.29 प्रतिशत और छोटी कंपनियों का निपटी स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.35 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, आईटी, रियलटी, तेल एवं गैस, रसायन और मीडिया समूहों के सूचकांक दो से तीन प्रतिशत के बीच चढ़े। ऑटो, वित्त, एफएएमसीसी, धातु, पफार्मा, बैंकिंग और स्वास्थ्य समूहों के सूचकांक एक से दो प्रतिशत तक मजबूत हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडियो का शेयर साढ़े चार प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहा। इटएल और पावरग्रिड में भी चार प्रतिशत से अधिक तेजी रही।

अर्थव्यापार चांदी रु. 239934

चावल, गेहूं के भाव बढ़े, चीनी नरम दालों और खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, वार्ता

घरेलू थोक जिस बाजारों में बुधवार को चावल का औसत भाव बढ़ गया। गेहूं में भी तेजी देखी गई, जबकि चीनी का भाव टूट गया। वहीं दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 33 रुपये बढ़कर 3,811 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गेहूं आठ रुपये महंगा हुआ और 2,778 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। आटे की कीमत 21 रुपये घट गई। दाल-दलहन में मिश्रित रुख देखा गया। चना दाल औसतन 12 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ, जबकि अन्य दालों में नरमी रही। उड़द दाल 67 रुपये और मसूर दाल 41 रुपये सस्ती



हुई। मूंग दाल की कीमत 40 रुपये और तुअर दाल की 88 रुपये प्रति क्विंटल घट गई। मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में जून का पाम ऑयल वायदा आठ रिगिट चढ़कर 4,474 रिगिट प्रति टन पर पहुंच गया। इसका अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.69 प्रतिशत की बढ़त में 66.90 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में ज्यादातर खाद्य तेलों में नरमी देखी गई। पाम ऑयल औसतन 204 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया। मूंगफली तेल 128 रुपये और सूरजमुखी तेल 93 रुपये सस्ता हुआ। वनस्पति की 82 रुपये और सरसों तेल की 34 रुपये फिसल गया। सोया तेल की कीमत 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई। मीठे के बाजार में आज गुड़ का औसत भाव 76 रुपये प्रति क्विंटल घट गया। चीनी 26 भी 35 रुपये सस्ती हुई। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे: दाल-दलहन: दाल चना 7659.32 रुपये, मसूर काली 8040.86 रुपये, मूंग दाल 10137.03 रुपये, उड़द दाल 10764.82 रुपये, तुअर दाल 11227.98 रुपये प्रति क्विंटल। अनाज: (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2778.13 रुपये और चावल 3811.05 रुपये प्रति क्विंटल और आटा (गेहूं) 3262.84 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

योगी ने टाटा मोटर्स लखनऊ संयंत्रा से बनी 10 लाखवीं गाड़ी को हरी झंडी दिखाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टाटा मोटर्स के लखनऊ संयंत्र में बनी 10 लाखवीं गाड़ी को हरी झंडी दिखाई और इसे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य को 'ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि किसी भी संस्था का समूह को मजबूती के लिए बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप से बचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बनाने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए हर कार्मिक का दायित्व है कि वह संगठन को परिवार की तरह समझे और उसकी एकता व विश्वास को बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने कार्यसंस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की सफलता टीमवर्क, ईमानदारी और कृतज्ञता पर आधारित होती है। हर कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही भाव दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित करता है।

संयंत्र ने... मुख्यमंत्री संयंत्र चौधरी ने फिलहाल अपने पास रखे हैं। जनता दल यूनाइटेड के खाते में फिलहाल 18 विभाग ही आए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन-संपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को ग्रामीण विकास, परिवहन, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय सहयोग करें: योगी

लखनऊ, वार्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पत्र लिखकर सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संतुलित और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी पहल है। योगी ने अपने पत्र में कहा कि आजादी के अमृतकाल में 'नया भारत' समावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति इस संकल्प का एक महत्वपूर्ण आधार है और महिला आरक्षण कानून इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। योगी ने कहा कि दशकों से संसद और



विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर व्यापक विमर्श होता रहा है, लेकिन वर्ष 2023 में इस कानून का लागू होना भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 16 अप्रैल से संसद के दोनों सदनों में इस कानून पर चर्चा प्रस्तावित है, जो 2029 के लोकसभा चुनाव से इसके प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत मजबूती मिलेगी, बल्कि शासन-व्यवस्था में नया दृष्टिकोण, अधिक संवेदनशीलता और व्यापक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित

होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण का मुद्दा किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आधी आबादी के अधिकारों और भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी बताते हुए कहा कि विमर्श से जुड़ा विषय है। आने वाली पीढ़ियों को कैसे लोकतंत्र सौंपना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण कानून को लेकर सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की अपील की है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसद में व्यापक और सार्थक चर्चा आवश्यक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि उनकी पार्टी इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन विचार-विमर्श करते हुए संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावित संशोधनों के समर्थन में रचनात्मक भूमिका निभाए।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में विधायक अभय सिंह समेत सभी छह आरोपी बरी

वाराणसी, वार्ता

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष न्यायालय (एमपीएमएलए) के न्यायाधीश यशुवंदर विक्रम सिंह को अदालत ने बुधवार को लगभग 24 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के सभी छह आरोपी बरी पियों को संदेश का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया था कि चार अक्टूबर 2002 को वाराणसी से जौनपुर लौटते समय उन पर नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास अत्याधुनिक हथियारों से प्राणघातक हमला किया गया था। हमले में धनंजय सिंह, उनके चालक, गनर समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। हमलावर मौके से पकड़ार हो गए थे। इस मामले में गौसाईंजि विधायक अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय

सिंह, विनीत सिंह (एमएलसी), विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को आरोपी बनाया गया था। विधायक अभय सिंह ने पकड़वरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सच्चाई की जोर हुई है। हम सभी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। 24 वर्षों से हम सभी को पकड़वरी मामले में पकड़वरी था। आज इंसाफ का दिन है। एमएलसी विनीत सिंह ने कहा कि न्यायालय पर हम सभी को पूर्ण विश्वास था कि एक दिन सत्य सामने आ जाएगा। मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। गलत तरीके से मेरा नाम शामिल किया गया था। यह न्याय और सत्य की जीत है। झूठ बेनकाब हो गया है। पकड़वरी को लेकर न्यायालय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करीब दहाई दशक तक चले इस हाईप्रोफाइल मामले के पकड़वरी के बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल मच गई है।

काम कोर्स उदास क्यों? अधिक सतुष्टि, हैसियतपूर्ण पावर, शीघ्रप्रतिक्रिया, गुणवत्ता, बचपन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा। फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।

श्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है आज ही इलाज करा लेना खई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें। काजीजादा, अमरोहा-UP 9997161320, 8272800800

Cipzer HEALTH WITH CARE जॉइन्ट्स क्योर लिवर का जिगरी दोस्त मूख की कमी, बढ़ती जाइन्ट्स, फेटी लीवर, एलर्जीकल लिवर फ़िज़ीय आदि से रक्त की ताकत देता है ताकि आप रैपिड एण्ड एफ़ेक्ट प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। 86 8484 5757 info@cipzer.com

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम : सीएम धामी

कहा, महिलाओं की शक्ति, साहस व समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार

मुख्यमंत्री ने किया नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की मातृशक्ति के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक युगांतकारी कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है।

बुधवार को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा राजकीय दूर मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल संख्या बढ़ाने का



प्रयास नहीं बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ नारी शक्ति को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है शिव भी तभी समर्थ हैं जब वे शक्ति से युक्त हों, शक्ति के

विना कोई भी सृजन या सामर्थ्य संभव नहीं हो सकता है, इसलिए नारीशक्ति के सामर्थ्य को बिना राष्ट्र और समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना असंभव है। उन्होंने कहा कि आज की महिला, किसान भी है, तो स्टार्टअप खड़ा करने वाली एंटरप्रेन्योर भी है। वो गाँव की पंचायत में विकास की योजनाएँ बनाने वाली जनप्रतिनिधि भी है, तो देश की संसद में नीति निर्धारण

करने की क्षमता रखने वाली सशक्त नेतृत्वकर्ता भी है। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे देश की आधी आबादी को वो सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसकी वो वास्तव में हकदार है। परन्तु अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार दिलाने की दिशा में एक नए युग का शुरुआत हो चुका है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 11 महिलाओं को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कडवाल, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना, पद्मश्री माधुरी बर्धवाल, भाजपा नेता दीपिका रावत, रूचि भट्ट सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहें।

महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में शिक्षा, रोजगार उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही, 'सशक्त बहना उत्सव योजना' और 'मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना' के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना' के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू लोबल' की पहल के अंतर्गत, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नाम से अम्ब्रेला ब्रांड को शुरुआत की गई है। राज्य सरकार को प्रयासों से प्रदेश की 2 लाख 65 हजार से अधिक लक्ष्यपति दीदीयों की सालाना आय एक लाख से अधिक हो चुकी। प्रदेश सरकार ने जहाँ एक ओर महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया वहीं, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 'समान नागरिक संहिता' लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र प्रस्तावित है। कई दशकों से लंबित महिला आरक्षण का सपना अब साकार होने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित भी किया।



नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के भविष्य को दिशा देने वाला परिवर्तनकारी प्रयास : सावित्री

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत के भविष्य को दिशा देने वाला परिवर्तनकारी प्रयास है। महिलाओं को संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार मिलेगा। अब महिलाएँ भी हर बड़े फैसलों में प्रभावी भूमिका निभाएँगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से महिलाओं का सम्मान, अधिकार और विश्वास में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला नेतृत्व को प्रार्थमिकता दी है और उनका सशक्तिकरण किया है। उन्होंने कहा महिलाओं की यात्रा केवल अधिकारों की नहीं अपितु आत्म सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तय करने की भी है।

महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया

का केंद्र बनाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम : रेखा आर्य

महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस कानून की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व नहीं देता, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्र बनाता है। अब महिलाएँ स्वयं नीतियाँ बनाएँगी, अपने अनुभवों के आधार पर समाज को दिशा देंगी। यही वास्तविक सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों की महिलाओं को अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए अक्सर पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें अक्सर सीमित मिले, मंच सीमित मिले, और निर्णय लेने के अधिकार भी सीमित रहे। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

राज्यपाल के सामने 'विधि सहयोगी' एप का प्रस्तुतीकरण

आमजन को मिलेगी सरल कानूनी सहायता

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष बुधवार को सांभल सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट ने 'विधि सहयोगी' मोबाइल एप का प्रस्तुतीकरण दिया।

उन्होंने बताया गया कि 'विधि सहयोगी' एक एआई सक्षम मोबाइल एप है, जो आम लोगों को सरल भाषा में कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विधिक सहायता तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एप के माध्यम से उपयोगकर्ता कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अध्ययन सामग्री हासिल कर सकेंगे और



आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों से संपर्क भी कर सकेंगे। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि भविष्य में इसमें ऑनलाइन परामर्श, केस ट्रैकिंग, दस्तावेज प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएँ भी जोड़ी जाएंगी। कुलपति ने बताया कि इसपर कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। राज्यपाल ने एप को तैयार करने वाली टीम एवं

विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवाचार समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, विधि परामर्शी कौशल किशोर शुक्ल एवं अपर सचिव रीना जोशी उपस्थित रहे।

शानदार पहल: राज्य के हर स्कूल में बजेगी वॉटर बेल

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्दान ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राई गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बचाव सुनिश्चित हो। मुख्य सचिव ने बुधवार को ग्रीष्मकाल में हीटवेव की तैयारियों को लेकर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विद्यालय के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वॉटरलेजर, ओआरएस एवं आवश्यक दवाओं का भंडारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव सम्बन्धी व्यावहारिक जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में



प्रत्येक छात्र-छात्राई को गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर मिलेगा पानी के लिए पानी, डिहाइड्रेशन से बचाव होगा सुनिश्चित

बढ़ते तापमान एवं संभावित हीट वेव की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मियों के

मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो, वहां सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बसों, स्टेशनों, बाजारों में शूड प्रोजेक्ट को व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक सभी विभाग समन्वित एवं सक्रिय रूप से कार्य करें। प्रत्येक जगह पर हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए संवेदनशील (हॉटस्पॉट) क्षेत्रों की पहचान की जाए तथा वहां विशेष निगरानी एवं राहत व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही 24x7 कंट्रोल रूम संचालित कर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। मुख्य सचिव ने पेयजल की उपलब्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंड, पंचायत भवनों आदि पर स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जल क्षेत्रों में जल संकट की संभावना है, वहां अग्रिम कार्ययोजना बनाकर टैंकरो की व्यवस्था, नलकूपों एवं पंपिंग सिस्टम की नियमित निगरानी तथा वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था तैयार रखी जाए। उच्च मांग की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सीसीएफ सुशांत कुमार पटनायक, डॉ. परम मधुकर धकाते, सी. रविशंकर, विनोद कुमार सुमन एवं रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज हर्षिल दौरे पर

शाह टाइम्स संवाददाता

उत्तरकाशी। जनपद के सीमांत क्षेत्र हर्षिल में भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को वह दोपहर 12:10 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से हर्षिल सेना हेलीपैड पर उतरेंगे। दौरे के दौरान सीडीएस 'चाइब्रेट विलेज योजना' के अंतर्गत स्थानीय किसानों के लिए एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास करेंगे और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके बाद वह हर्षिल स्थित ऐतिहासिक विल्लम हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।

सीडीएस का यह दौरा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हर्षिल के आगे निलांग और जादुंग जैसे क्षेत्र भारत-चीन सीमा की अग्रिम चौकियों के रूप में संवेदनशील माने जाते हैं। इस दौरे से जहां सीमांत सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी, वहीं क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है।



प्रदेश में 50 स्विफ्ट स्कूलों का होगा शुभारंभ: डॉ. रावत

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में 50 'स्विफ्ट स्कूल' स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शिक्षा विभाग एवं कॉन्वर्जिनियस फाउण्डेशन के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। जिसके तहत इन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल अवसरचना विकसित की जायेगी। साथ ही कॉन्वर्जिनियस फाउण्डेशन एमेजन वेब सर्विस से सहाय्योग से छात्र-छात्राई को 1000 लैपटॉप भी वितरित करेगा। स्विफ्ट स्कूलों की स्थापना के लिये विभाग द्वारा स्कूलों का चयन कर लिया गया है, साथ ही विभागीय



अधिकारियों को स्वीफ्ट स्कूलों के शीघ्र संचालन को निर्देश दे दिये गये हैं। सबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को तकनीकी आधारित बनाने के लिये निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में

शिक्षा विभाग व कॉन्वर्जिनियस फाउण्डेशन के बीच हुआ एमओयू साइन

सीएसआर फंड से छात्र-छात्राई को 1000 लैपटॉप

समग्र शिक्षा एवं कॉन्वर्जिनियस फाउण्डेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। जिसके तहत प्रदेशभर में 50 'स्विफ्टस्कूल' की स्थापना की जायेगी। डॉ. रावत ने बताया कि 'स्विफ्ट स्कूल' एक एकीकृत विद्यालय परिवर्तन मॉडल है। जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग, शिक्षकों को डेटा आधारित सहायता के साथ ही डिजिटल अवसरचना का समावेश होगा। जिससे छात्र-छात्राई को उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा देने में मदद मिलेगी साथ ही शिक्षकों को डेटा आधारित जानकारी मिलेगी जिससे वह कक्षा में अधिक प्रभावी अध्यापन कर सकेंगे। स्विफ्ट स्कूलों में तकनीकी के माध्यम से बच्चों के सीखने की कर्मियों की समय पर पहचाना कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी। बताया कि कॉन्वर्जिनियस फाउण्डेशन प्रदेश में सीएसआर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद कर रहा है।

सीडीएस भर्ती के रिक्त पदों के लिए अध्यायन भेजे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। अपर सचिव, कार्मिक एवं सतकता गिरधारी सिंह रावत ने उपनल के माध्यम से कार्ययोजित किये जाने वाले कर्मियों के सापेक्ष सीडी भर्ती के रिक्त पदों के लिए अध्यायन भेजे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों व जिलाकारियों को सम्बोधित पत्र में स्पष्ट किया है कि विभागों के अन्तर्गत सीडी भर्ती के ऐसे पद, जिनके सापेक्ष सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनार्थ 03 फरवरी, 2026 में जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों के आलोक में उपनल

अपर सचिव, कार्मिक व सतकता ने जारी किए निर्देश

कर्मियों को रखा जायेगा, उन पदों के सापेक्ष सीडी भर्ती के रिक्त पदों के समस्त अध्यायन/प्रस्ताव चयन संस्था/आयोग को भेजने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा कार्मिक एवं सतकता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा बिना आवश्यक पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का भर्ती प्रस्ताव अग्रसारित न किया जाए।

खेल प्रतिस्पर्धा का माध्यम व व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार: धामी

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को परेड ग्राउंड, देहरादून स्थित बहुदेशीय क्रीड़ा हॉल में 87वें इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया।

मुख्यमंत्री ने किया 87वें इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ



खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार है। खेलों के माध्यम से अनुशासन, धैर्य, टीम भावना और लक्ष्य के प्रति समर्पण जैसे जीवन-मूल्य विकसित होते हैं, जो युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे न केवल अपने-अपने राज्यों का बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी

मेहनत, अनुशासन और संकल्प ही भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेबल टेनिस ऐसा खेल है जिसमें गति, संतुलन, तकनीक और मानसिक दृढ़ता का समन्वय आवश्यक होता है। यह खेल खिलाड़ियों को त्वरित निर्णय क्षमता, रणनीतिक सोच और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल,

कहा, राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने करने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के माध्यम से उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ खेलभूमि के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि खिलाड़ियों का जज्बा, अनुशासन और आत्मविश्वास ही उन्हें सच्चा विजेता बनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारत ने खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज देश वैश्विक मंचों पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों एवं कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के लिए गर्व का विषय है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है। 'खेलों इंडिया' एवं 'फिट इंडिया

नारियों को अपना अधिकार लेने से अब कोई रोक नहीं पाएगा: भट्ट

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। भाजपा ने गुरुवार से होने वाले संसद के विशेष सत्र को आधी आबादी को उसके पूरे अधिकार देने की दिशा में इतिहास सृजन करने वाला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मातृ शक्ति को संवैधानिक अधिकार देने का यही समय है, सही समय है। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष को भी सुझाव दिया कि राजनैतिक विरोध छोड़ें और महिला आरक्षण संशोधन बिल का समर्थन करें। क्योंकि देश की नारियों को अपना अधिकार लेने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने मीडिया को माध्यम दी गई अपनी प्रतिक्रिया कहा, मातृ शक्ति को समुचित संवैधानिक अधिकार देने में देश पहले से ही



पीएम के नेतृत्व में आधी आबादी को पूरा अधिकार देगी संसद : भाजपा

बहुत पीछे है। ऐसे में 2023 में पास इस नारी शक्ति वंदन कानून को तय समय से पहले ही 2029 लागू करने की कोशिशों पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो भी तब जब विपक्ष इसे 2024 के चुनावों से ही लागू करने की मांग करता रहा हो। लिहाजा देश अच्छी तरह तरह देख समझ रहा है कि जल्दी लागू करने

के प्रयासों का विरोध क्यों हो रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिला आरक्षण में एएससी एसीटी तरह, कानून में ओबीसी को शामिल करने की बहस छेड़ना पूरी तरह से महिला अधिकारों की रेल को डिरेक्ट करने की तैयारी बताया। क्योंकि सभी जानते हैं कि संवैधानिक जनप्रतिनिधित्व में ओबीसी आरक्षण देना संविधान प्रावधानों में नहीं है। जिसको लेकर विस्तृत चर्चा मूल कानून के पास होने के दौरान हुई थी, तब सभी ने वर्तमान कानून को पास किया था। ऐसे अब दोबारा से इस चर्चा को करना, कहीं न कहीं कानून संशोधन को बाधित करना है। वहीं परिसीमा को लेकर आने वाले संशोधन को भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण की इस कोशिश में बेहद अहम बताया।

बाजार में दस्तक देगी 'कौसानी चाय'

जिलाधिकारी आकांक्षा ने शुरू कराया पैकेजिंग कार्य

शाह टाइम्स संवाददाता
बागेश्वर। जिलाधिकारी आकांक्षा कोड़े द्वारा बुधवार को कौसानी चाय की स्थानीय स्तर पर पैकेजिंग व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ कौसानी चाय को पैकेजिंग का कार्य करेंगी, जिससे स्थानीय उत्पाद को बाजार में बेहतर पहचान और उचित मूल्य मिल सकेगा। डीएम ने कहा कि कौसानी चाय में अपार संभावनाएँ हैं और इसकी सही ब्रांडिंग व पैकेजिंग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से उत्पाद के पीछे की सोच और उद्देश्य को समझते हुए एक मजबूत विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। यह एक शुरुआत है और आगे सभी



आवश्यक कदम योजनाबद्ध तरीके से पहुँच सके। इस अवसर पर जिला, को सशक्त बनाने और उन्हें बाजार तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ होगी और उत्पाद को उसका उचित मूल्य एवं पहचान मिल सकेगा। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीओ शिल्पी पंत ने बताया कि क्लस्टर स्तरीय संकल्प के माध्यम से मार्केटिंग में सहायता के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि महिलाओं में मार्केटिंग को लेकर जो भी समस्याएँ आ रही हैं उसका समाधान हो सके। बैठक में परियोजना प्रबंधक मोहम्मद अरिफ समेत संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ उपस्थित रही।

धिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहल रीप एवं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों

दौरा के जंगल में धधकी आग, काबू पाया
अल्मोड़ा। जिले में गमाँ बहने के साथ ही वनाजि की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। बीते मंगलवार रात दौरा गाँव के जंगल में आग धक उठी। सूचना पर फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा के जंगलों में वनाजि की घटनाएँ शुरू हो गई हैं। ग्राम पंचायत दौरा के जंगलों में मंगलवार रात अचानक आग धक उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से विराहशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों में ही हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर सर्विस को दी। अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुँची फायर सर्विस की टीम ने एक हाथी रील फँसकर आग पर काबू पाया शुरू किया।

देहरादून में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे महापौर दीपक बाली

शाह टाइम्स संवाददाता
काशीपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे महापौर दीपक बाली भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री रॉडर मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने यहां पहुंचे थे, जिसे उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के उपरान्त पीएम मोदी के साथ महापौर बाली ने भी प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से विदाई दी। महापौर दीपक बाली ने इस अवसर को उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

किसानों ने विद्युत विभाग से मांगा मुआवजा

शाह टाइम्स संवाददाता
काशीपुर। ग्राम कुआंखेड़ा में किसानों के गेहूँ के खेत में आग लगने के बाद 220 क्वी लीटर का मरम्मत करने आए बिजली कर्मियों का विरोध करते हुए किसानों ने पीड़ित किसान को मुआवजा मिलने का ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक मरम्मत कार्य शुरू न करने देने की चेतावनी दी। विदित हो कि सोमवार को ग्राम कुआंखेड़ा में विजान वैली स्कूल के पास दो किसानों के गेहूँ के खेतों में हाईटेंशन लाइन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग जाने से किसानों की 12 एकड़ खेत में लगी गेहूँ की फसल जलकर राख हो गई थी। मंगलवार को पिटकुल के 11 नवीन प्रसन्न कर्मचारियों के साथ लाइन प्रसन्न कराने पहुंचे, लेकिन



किसानों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले किसानों को हूए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। बताया कि पीड़ित किसानों के खेत में पहले भी दो बार आग लग चुकी है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। भागीपुत सिंह के प्रेक्ष प्रवक्ता मनप्रति सिंह ने मौके पर

एक नजर...

विद्युत विभाग की लापरवाही का दंश झेल रहे किसान: डा. गणेश उपाध्याय

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। उधम सिंह नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण गेहूँ की फसल में आग लगने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। इस लापरवाही के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डा. गणेश उपाध्याय ने इस संबंध में कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही को वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द विद्युत विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। डा. उपाध्याय ने यह भी कहा कि किसानों को उनका फसल को नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, और उत्तराखंड सरकार को प्रति एकड़ रुपये 40,000 को मुआवजा देने का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने शीघ्र ही कोई कदम नहीं उठाया, तो किसान एक जुट होकर विद्युत विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।

बीडीओ ने खड़े कराए सरकारी वाहन

कालाहूरी। बुधवार को कोटाबाग के सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग पांडे द्वारा सीडीओ से की गई रिप कर्मचारियों की शिकायत के बाद सीडीओ अरविंद कुमार पांडे ने कोटाबाग खंड विकास अधिकारी डा. श्वेता को तत्काल सरकारी वाहन ब्लॉक में ही खड़ा करने के आदेश दिए। जिसके बाद बीडीओ ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए कोटाबाग ब्लॉक के रीप कर्मचारियों को दो सरकारी मोटर साइकिल जिसमें एक वाहन तो दूसरी स्कूटी को कोटाबाग ब्लॉक में खड़ी करवा दी और चाबी स्टोर प्रभारी को सौंप दी। सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ ने सभी रिप कर्मचारियों को आदेशित किया कि भविष्य में फील्ड के किसी भी कार्य में जाने से पहले बीडीओ की परमिशन आवश्यक है। बीडीओ ने रीप कर्मचारियों को फील्ड में जाने और आने का समय, जगह और फोटो बताने देने को कहा। अन्य शिकायत की जांच के लिए एपीडी को जांच अधिकारी बनाया गया।

बताया: कचरे को अलग-अलग कैसे रखें

काशीपुर। नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल जागरूकता अभियान के तहत जीपीएस बांसखेड़ा खुर्द एवं जीपीएस बांसखेड़ा कला में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने छात्र-छात्राओं को 6 बिन कचरा प्रोग्राम के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न गतिविधियों एवं खेल के माध्यम से उन्हें कचरे को सही तरीके से अलग-अलग डिब्बों में डालने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं को स्वच्छता सार्विक रिक्तियों एवं 6-बिन से संबंधित स्टिकर्स वितरित किए गए, जिससे वे अपने घरों में भी इस संदेश को आगे बढ़ाकर अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक कर सकें। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें जागरूक नागरिक के रूप में तैयार करना है, ताकि वे आने वाले समय में स्वच्छता के प्रेरक बन सकें।

अव्यवस्थाओं पर फार्मासिस्टों का विरोध

बागेश्वर। चारधाम यात्रा ड्यूटी के दौरान आ रही समस्याओं को लेकर हिल्दोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, बागेश्वर ने चरमबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। बुधवार को कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन भत्ता का मुताबिक अब तक लंबित है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्टों के लिए भत्ता और आवास की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई है। फार्मासिस्टों ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार महिला फार्मसी अधिकारियों को भी ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि पहले केवल पुरुष कर्मचारियों को तैनाती की मांग की गई थी। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया।

पंडा वंशगोपाल अग्निहोत्री का निधन

काशीपुर। माता बाल सुन्दरी देवी मंदिर के पंडा वंशगोपाल अग्निहोत्री का आज एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि लगभग 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद भी पक्काकाट स्थित उनके निवास पर शोक संवेदन व्यक्त करने वालों का ताता लगा हुआ है। पंडा वंशगोपाल अग्निहोत्री माता बाल सुन्दरी देवी मंदिर से जुड़े धार्मिक कार्यों का संचालन कर रहे थे। चैती मेले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी और वे श्रद्धालुओं के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति मानी जा रही है। क्षेत्रवासियों ने उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

वृक्षारोपण के भूमि आवंटन प्रस्तावों की समीक्षा

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अर्थिकता में विकास भवन सभागार में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण में शिथिलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

सूचना: नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम प्रीति खुराना से बदलकर प्रीति अरोड़ा (PREETIARORA) कर लिया है। भविष्य में पुत्रे PREEETIARORA (प्रीति अरोड़ा) के नाम से जाना व पहचाना जाए। प्रीति अरोड़ा पत्नी राजेन्द्र अरोड़ा, बार्ड 9, आवास विकास, किच्छा (उधम सिंह नगर)।

NAME CHANGE

I, AZEEM AHMAD have changed my name from AJIM AHAMAD to AZEEM AHMAD hence forth I shall be known as AZEEM AHMAD S/O JALIL AHAMAD R/O Ward-15, Dakbangla, Bazpur, Udhm Singh Nagar, UK.

मोनिका रावत बनी 'ब्लैक कैट कमांडो' एनएसजी में हुआ चयन

शाह टाइम्स संवाददाता
काशीपुर। मोनिका रावत ने अपनी मेहनत और लगन से एनएसजी में विशेष कमांडो के रूप में चयन प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मोनिका रावत स्व. हवलदार जसपाल सिंह रावत की पुत्री हैं, जो मूल रूप से पीडो गढ़वाल के ब्लॉक नैनीडांडा के ग्राम मजेडा की निवासी हैं और वर्तमान में काशीपुर की सैनिक कालोनी में रहती हैं। मोनिका रावत वर्ष 2022 में असम राइफल्स में भर्ती हुई थीं और अपनी सेवा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन एनएसजी के लिए हुआ। वे तीन बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनका एक छोटा भाई भी



है। मोनिका रावत के पिता स्व. जसपाल सिंह रावत भी असम राइफल्स में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उनके चाचा हर्षपाल रावत भी असम राइफल्स में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। नेशनल सिस्कोरिटी गार्ड (एनएसजी) देश की एक विशिष्ट आतंकवाद-रोधी सुरक्षा इकाई है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसमें सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि चयन भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों में से किया जाता है।

आर्थिक आधार पर लागू हो आरक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता
अल्मोड़ा। अखिल भारतीय कल्याणकारी संस्था अल्मोड़ा की बैठक बुधवार को नगर के एक होटल सभागार में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय समस्तियों और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई गई। संस्था ने कहा कि पूरे देश में आरक्षण को व्यवस्था आर्थिक आधार पर ही होनी चाहिए, जिसके लिए वह लगातार शासन-प्रशासन को अवगत कराती रही है। इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में झुलते बिजली के तारों को शीघ्र ठीक कराने की मांग उठाई गई। संस्था ने चेतावनी दी कि ढीले तारों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों के उचित जल निकास और नियमित रखरखाव पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने और अक्ललाइन प्रक्रियाओं को अनिवार्य न बनाने की मांग भी रखी गई। बवारव से पेटशाल मोटर मार्ग को शीघ्र निर्माण, जंगली जानवरों और आवागमन पशुओं की रोकथाम, विशेषकर बंदरों के बंधनकारण और बाढ़ा निर्माण की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बैठक में नगर निगम से पेयजल, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुचारु व स्वच्छ बनाए रखने की अपील की गई। वहीं ग्राम पंचायत विन्तोला में पिछले दो महीनों से पेयजल संकट और अशुभ तारबांध निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। अध्यक्ष जमन सिंह देवड़ी, महासचिव लक्ष्मण सिंह बोर, उप सचिव ह्यात सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष राम सिंह बिष्ट, संरक्षक डा. एएसएस पाटनी, आनंद सिंह सवाल, जसद सिंह बिष्ट, रुद्र सिंह बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर सिराडी, लाल सिंह मेहता समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

प्रधानों का प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन

शाह टाइम्स संवाददाता
बागेश्वर। जिला ग्राम प्रधान संगठन बागेश्वर ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने प्रशासनिक जटिलताओं, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना की कमी और विकास कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को प्रमुख समस्याएँ बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिले के सभी ग्राम प्रधान कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। बुधवार को संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक खेवावाल के नेतृत्व में कपकोट, गरुड और बागेश्वर ब्लॉक के ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण सामग्री दूर-दूर से ढोनी पड़ती है, जिससे आधी घनराशि परिवहन में ही खर्च

हो जाती है। प्रधानों ने मांग उठाई कि पुरानी कार्यप्रणाली के अनुसार ही विकास कार्य कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये के कार्य में जीएसटी और अन्य खर्चों के बाद मात्र 60 हजार रुपये ही बचते हैं, जिससे विकास कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने, मनरेगा और अन्य विकास कार्यों का लंबित भुगतान शीघ्र करने तथा मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 500 रुपये निर्धारित करने की मांग भी रखी गई। प्रधानों ने कहा कि वर्ष 2024-25 से कई विकास कार्यों का भुगतान लंबित है, जिससे मजदूरों को मजदूरी देने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सभी ग्राम प्रधान विकास कार्य बंद कर घराना-प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर गाोकूल पांचवाल, सुंदर मेहरा, बहादुर खाली, नवल किशोर, गीता देवी, आनंदी, सीमा देवी, दीपा देवी, चम्पा देवी, कला देवी, दीक्षा कोश्यारी, मीरा सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।



हो जाती है। प्रधानों ने मांग उठाई कि पुरानी कार्यप्रणाली के अनुसार ही विकास कार्य कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये के कार्य में जीएसटी और अन्य खर्चों के बाद मात्र 60 हजार रुपये ही बचते हैं, जिससे विकास कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने, मनरेगा और अन्य विकास कार्यों का लंबित भुगतान शीघ्र करने तथा मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 500 रुपये निर्धारित करने की मांग भी रखी गई। प्रधानों ने कहा कि वर्ष 2024-25 से कई विकास कार्यों का भुगतान लंबित है, जिससे मजदूरों को मजदूरी देने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सभी ग्राम प्रधान विकास कार्य बंद कर घराना-प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर गाोकूल पांचवाल, सुंदर मेहरा, बहादुर खाली, नवल किशोर, गीता देवी, आनंदी, सीमा देवी, दीपा देवी, चम्पा देवी, कला देवी, दीक्षा कोश्यारी, मीरा सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

अल्मोड़ा में लगेगा दुर्गा वाहिनी का विशेष वर्ग

शाह टाइम्स संवाददाता
अल्मोड़ा। नगर के आर्य कन्या इंटर कालेज में आगामी 29 मई से 5 जून तक दुर्गा वाहिनी का विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। विधिपूर्वक के केंद्रीय मंत्री दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ग में 200 से अधिक बहनों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजकों द्वारा कालेज परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायज लिया गया और प्रशिक्षण वर्ग के संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों पर चर्चा की गई। इस दौरान अत्याव, भोजन, सुरक्षा तथा प्रशिक्षण स्थलों की व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से योजना बनाई गई। आयोजकों ने बताया कि यह वर्ग बहनों के शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें आत्मरक्षा, अनुशासन, संगठन कौशल और राष्ट्र सेवा से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्रतिभागियों को सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के वर्गों से युवावर्गों में आत्मनिष्ठा बढ़ती है और वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए



रिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें आत्मरक्षा, अनुशासन, संगठन कौशल और राष्ट्र सेवा से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्रतिभागियों को सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के वर्गों से युवावर्गों में आत्मनिष्ठा बढ़ती है और वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए

प्रेरित होती हैं। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर उत्साह का माहौल है और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी सहयोग मिल रहा है। आयोजकों ने सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने का भरपूर जवाब दिया और कहा कि यह वर्ग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सफाई-साई, भोजन सज्जा, पेयजल, आवास और मंचन जैसी सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया

मनरेगा कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई में देरी

शाह टाइम्स संवाददाता
कालाहूरी। ग्राम पंचायत बांसी, ब्लॉक कोटाबाग, जनपद नैनीताल के निवासी भूपेंद्र सिंह ने मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत 10 अगस्त 2025 को सीएम हेलपलाइन पोर्टल पर की थी, लेकिन प्राथमिक जांच न तो ब्लॉक स्तर पर और न ही जिला स्तर पर की गई। 19 सितंबर 2025 को शिकायत लोकपाल (मनरेगा) को सौंपे जाने के बाद 8 अक्टूबर 2025 को जांच की गई, लेकिन शिकायतकर्ता को बिना सूचना दिए और उसकी अनुपस्थिति में जांच के दौरान कुछ अन्य व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना दिया गया, जिनका आरोप था कि उन्हें लो. कपाल ने धमकी दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा 14 नवंबर 2025 को लिखित उत्तर देने के बावजूद,

लोकपाल ने 18 नवंबर 2025 को 51,000 रुपये के अर्थदंड की घोषणा की, जिसके कारण शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा। 12 जनवरी 2026 को अपील दायर की गई, जिसमें पाया गया कि लोकपाल की कार्रवाई नियमों के खिलाफ थी। अपीलीय प्राधिकरण ने 51,000 रुपये के अर्थदंड को निरस्त कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शिकायत की प्रति साझा किए जाने और एफआईआर की धमकी दिए जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा न्यायसंगत निर्णय लेते हुए मामलों में उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक लोकपाल और विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

'सनम चौकीदार', 'नीलिमा' की भावपूर्ण प्रस्तुति

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। नई दिशाएँ ट्रस्ट के तत्वाधान में जयमोहन इंटर कालेज (कान्या) के ऑडिटोरियम में कुमाऊँ कौतिक एवं कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। 15 दिवसीय कार्यशाला के पाश्चात कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को मनमोहक झलक प्रस्तुत की गई, जिसमें सर्वप्रथम वंदना उत्तराखंड देव भूमि और पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य, झोड़ा, चांचरी, छपेली तथा एकल गायन की आकर्षक प्रस्तुतियाँ नई दिशाएँ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गईं। जिसके पश्चात झोड़ा, छपेली, सनम चौकीदार एवं गढ़वाली लोकनृत्य नीलिमा की सुंदर एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। एकल गायन में चंदन सिंह मेहरा की प्रस्तुति विशेष रूप से सराहनीय रही। कार्यक्रम का निदेशन भुवन जोशी द्वारा किया गया। सहायक निदेशन तरण पांडे ने संभाला। गायन में चंदन सिंह मेहरा, अमित चुषीरी एवं गायिका ज्योति उग्रती ने अपनी मधुर प्रस्तुति विशेष रूप से दर्शकों को जीता। साथ ही प्रतिभागियों को



सिंह मेहरा, अमित चुषीरी एवं गायिका ज्योति उग्रती ने अपनी मधुर प्रस्तुति विशेष रूप से सराहनीय रही। कार्यक्रम का निदेशन भुवन जोशी द्वारा किया गया। सहायक निदेशन तरण पांडे ने संभाला। गायन में चंदन सिंह मेहरा, अमित चुषीरी एवं गायिका ज्योति उग्रती ने अपनी मधुर प्रस्तुति विशेष रूप से दर्शकों को जीता। साथ ही प्रतिभागियों को

महिला उत्पीड़न मामलों में त्वरित कार्रवाई करें: डीएम

अल्मोड़ा। विकास भवन सभागार में कानून-व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, नियमित पुलिस, राजस्व पुलिस, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। विभागीय प्रगति, लंबित मामलों तथा राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए विशेष रूप से महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां कड़ी निगरानी रखने और अपराध होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किए गए वाहनों के समयबद्ध निस्तारण तथा प्रवर्तन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए, वहीं राजस्व मामलों तथा राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में निस्तारण पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री कोय से आर्थिक सहायता के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ राजजीतशरण शर्मा, एडीएम युक्ता मिश्र, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, एडिओएम संजय कुमार शर्मा

प्रस्ताव बनाते समय जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए

जिला योजना की तैयारी बैठक में अधिकारियों को डीएम रयाल के निर्देश

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। जिला योजना के प्रस्ताव बनाते समय जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, क्षेत्र के प्राथमिक कार्यों, स्वरोजगार परख योजनाओं, वर्तमान में चालू कार्यों को पूर्ण करने सहित क्षेत्रीय जरूरत को देखते हुए व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता से योजना में सम्मिलित किया जाए। बुधवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नैनीताल जिले की प्रस्तावित जिला योजना वर्ष 2026-27 को पूर्ण तैयारी बैठक लेते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए।



जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएं वे ऐसे हों जिनसे सीधे आम जनता को फायदा पहुंचे और धनराशि का सदुपयोग हो। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि विकास योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ सामान्य नागरिकों तक पहुंचे इस प्रकार की योजनाओं को प्रस्ताव में रखा जाए। उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उद्यान, कृषि मत्स्य, दुग्ध विकास पशुपालन आदि विभागों और आजीविका से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि डेप्युटी जिला योजना अधिकारी को अन्तर्गत जो कार्य और राज्य सरकार की योजनाओं से

मदिरा की दुकानों में मिली अनियमितताएं, चालान

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आबकारी विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।



स्थित विभिन्न मदिरा दुकानों पर छापेमारी की और गहन निरीक्षण किया। आबकारी विभाग की टीम ने काठगोदाम, नैनीताल रोड, तिकोनिया, लोहरियावाला, कुसुमखंडा सहित कुल 12 मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें स्टॉक रजिस्टर का सही तरीके से न भरा जाना, सीसीटीवी कैमरा बंद पाया जाना, और मदिरा के नए रेटों का रेट लिस्टर में अंकन न होना प्रमुख थीं। इन कमियों के आधार पर संबंधित दुकानों के चालान की कार्रवाई की गई और जिले के आबकारी अधिकारियों के समक्ष प्रश्नमन की संसृति की गई। इस दौरान सभी मदिरा दुकान विक्रेताओं और अनुज्ञापियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे केवल निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री करें और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को तुरंत ठीक करें, अन्यथा पुनः चालानी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, उप आबकारी निरीक्षक कैलाश चंद जोशी सहित कांस्टेबल चंद्रशेखर कांडपाल शामिल थे।

राज्य सरकार 6 सप्ताह के भीतर फिर से पेश करे

प्रगति रिपोर्ट: हाईकोर्ट नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हल्द्वीचूड में वर्ष 2014 में बनकर तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो वहाँ पर कमियाँ हैं उन्हें भी इस बीच पूर्ण करें। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने छः सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अन्तगत कराया गया कि अभी भी कई मूलभूत सुविधाएँ वहाँ पर मुहैया नहीं हैं। लैब महसिलीयन नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाएँ नहीं हैं जिसपर कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

पंचायती एक्ट के लिए ग्राम प्रधानों ने खोला मोर्चा, उठाई अहम मांगें

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और ग्राम पंचायतों के अधिकारों को लेकर बुधवार को ग्राम प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक ग्राम पंचायत खेड़ा गौलापार में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायती राज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हुंकार भरते हुए मोर्चा खोल दिया।



संगठन ने चेतावनी दी कि अगर पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाएं और लॉबिंग समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को अधिकार मिलना लोकतंत्र की मूल भावना के

आवृत्त करने की मांग की। बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर शासन-प्रशासन ने इन जायज मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया, तो विभाग खंड और जिला मुख्यालय स्तर पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में ग्राम प्रधान उमा नीरज रेवाला, तारेश बिष्ट, भीम सिंह बिष्ट, चित्रा हरिश बिष्ट, हेमू पडालिया, महेश चंद्र भट्ट, किशन सिंह दम्वाल, अर्चना बिष्ट, सुनीता बिष्ट, चतुर सिंह, गीता बुधानी, ज्योति चौधरी, गणेश प्रसाद, तुलसी बिष्ट, राजू आर्य, दीपा आर्या, युसुना सनवाल, यशवंत सिंह बिष्ट, रुक्मिणी नेगी, नरेश सिंह, पूजा बिष्ट, दिनेश चंद्र जोशी, रमेश चंद्र, प्रदीप कुमार, हिमांशु आर्य, सोनिया प्रीत, सुनीता बंगली, गीता डोगरा, यशोदा मनवाला सहित कई अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

चारधाम यात्रा का किया बहिष्कार

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। चारधाम यात्रा ड्यूटी के दौरान पिछले दो वर्षों का यात्रा भत्ता, (टीए, डीए) का भुगतान न होने और यात्रा के दौरान बेहतर रहने की व्यवस्था को भी लेंकर बुधवार को डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की कुमाऊं मंडल शाखा के आह्वान पर जनपद के सभी चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मसी अधिकारियों ने हाथ में काला फीता बांधकर आंदोलन शुरू कर दिया। डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही मांगों को पूरा

नहीं किया गया तो वह चार धाम यात्रा का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। पहले दिन आंदोलनकर्ता संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी उचित मांगों का समाधान नहीं किया जाता, वे अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल टीए, डीए का भुगतान और यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 15 मई से चार धाम यात्रा का बहिष्कार किया जायेगा। इस दौरान संगठन के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष पवन पाण्डेय, मंडलीय कोषाध्यक्ष दिगम्बर रावत, अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, मंत्री नन्दन गोस्वामी, जगदीश टाटा, दीपक शर्मा, आईके आर्या, डीएस कोश्यारी, विनोद पाण्डेय, गिरीश पाण्डेय, कमलेश कुमार, मनोहर मेहता, पुष्पा, शशिपाल गोस्वामी, मदन गोस्वामी, एनके जोशी सहित कई फार्मसी अधिकारी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट में शोक सभा

शाह टाइम्स ब्यूरो
नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बुधवार को शोक सभा आयोजित अधिकारिता श्याम सुन्दर चौधरी, पान सिंह बिष्ट, रितेश पंत, रोहित कक्कड़ की माताओं व अजयवीर सिंह पुण्डरी, खुशी चौधरी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। शोक सभा को अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने की और संचालन महासचिव सौरभ अधिकारी द्वारा किया गया। सभा में उपाध्यक्ष गौरव काण्डपाल, मीना बिष्ट, भुवनेश्वर जोशी, डीएस मेहता, योगेश पंचोल्या सहित एसोसिएशन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी संख्या में अधिकारिता मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों ने तीन दिन का दिया अल्टीमेटम

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। लॉबिंग पट्टी 15 सूत्रीय मांगों का समाधान ना होने पर नाराज देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने बुधवार को नगर निगम परिसर में निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने एलान किया कि अगर तीन दिन के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। बुधवार को देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के वैनर लले दर्जनों कर्मचारी एकत्र हुए और लॉबिंग पट्टी मांगों को पूरा करने की मांग की। धरना स्थल पर हुई सभा पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुए समझौते के बावजूद एसपीओ का लाभ अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे



कर्मचारियों में हठरा आक्रोश व्याप्त है। वक्ताओं ने कहा कि पिछले सात माह में सात बार रिमांडर दिए जाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन द्वारा मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि

आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में उठे जाने की भावना उत्पन्न हो रही है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन को होगी। धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह, उपाध्यक्ष अमरदीप वाल्मीकि, शाखा अध्यक्ष अशोक चौधरी, महामंत्री श्याम सुंदर सहित विजय तोमर, विशाल, सिद्धार्थ, चंदन बजारी, रोहित, राजेश भारती, बलवीर, राजेश खन्ना, प्रमोद, रुपेश, पंडु रहा है। कर्मचारियों ने सरकारी जमानत के अंतर्गत एसपीओ को निलंबित करने की मांग की।

बड़ी सफलता: पुलिस ने पकड़ी 66 लाख की रकम

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। ऑपरेशन प्रहार के तहत बीती रात्रि वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने युवाओं में नशीला जहर



एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाल विजय मेहता व एसओजी प्रभारी राजेश जोशी की अगुवाई में टीम भोदिया पड़ाव क्षेत्र में वाहन चैकिंग कर रही थी तभी एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन युवक टीम को देख भगने लगा। शक होने पर टीम ने घेराबंदी करते हुए युवक को दबाव

गुलाटी चिकन वाली गली में किराए पर रहता है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली व मुसौली में एक-एक मुकदमा दर्ज है। एसएसपी ने गुडवर्क करने वाली टीम को 15 सौ रूपये इनाम की घोषणा

राजपुरा व बनभूलपुरा में दो स्मैक तस्कर गिरफ्तार
हल्द्वानी। नशीले खिलोफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजपुरा व बनभूलपुरा पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजपुरा चौकी प्रभारी कृष्ण गिरी मय टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तभी गौला पट्टी राजपुरा के पास से गुलशन पट्ट स्व. छुट्टन निवासी राजपुरा वार्ड नंबर-13 बतया। जिसके कब्जे से 4.18 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जबकि दूसरी और बनभूलपुरा कोतवाली में तैनात एसआइ मनोज यादव मय टीम के साथ क्षेत्र में चैकिंग कर रहे थे तभी चोरगलिया रोड के पास एक युवक संदिग्ध दिखाई दिया जो टीम को देख भगने लगा। शक होने पर टीम ने घेराबंदी करते हुए उसे दबाव लिया। जिसकी तलाशी के दौरान 11.72 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने अपना नाम मेराज अली पुत्र मो. हनीफ निवासी चोरगलिया रोड लाइन नंबर-18 वार्ड नंबर-24 बनभूलपुरा बतया। पकड़े गए तस्कर मेराज अली के खिलाफ पूर्व में पांच मुकदमों भी दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया।

व्यापार मंडल ने संगठन में वरिष्ठ नागरिकों को दी जगह

शाह टाइम्स ब्यूरो
हल्द्वानी। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल ने संगठन को मजबूती के उद्देश्य से कारोबारी और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में दायित्व निभा रहे प्रबुद्धजनों को अपने संगठन में शामिल किया है। संरक्षक मंडल में मां बराही धाम के लक्ष्मण सिंह लमगाडिया, गल्ला मंडी के कारोबारी लक्ष्मी चंद्र आसवानी, भगवान लक्ष्मी, भुवन तिवारी, प्रकाश हर्बाला को शामिल किया है। सलाहकार मंडल में कैची धाम से सुद्धे और प्रकाश बिंद्रा, स्टोन क्रशर संघ के पूर्व

अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नीरज शारदा, थाल सेवा से जुड़े गिरीश गुप्ता, रमेश चंद्र बिष्ट, संजय अग्रवाल टाट्ट, हिमालया चैबर कामर्स के सचिव मनोज डोगा और स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष धनश्याम रस्तोगी को शामिल किया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में कैमिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष राज. कुमार अग्रवाल, लालकुआं के वरिष्ठ व्यापारी नेता भुवन पांडे, पूर्व सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान, शक्तिफार्म के व्यापारी नेता अजय सिंह, अरुणोदय संस्था के जितेंद्र रौतेला, क्रियाशाला डहरिया से जुड़े नवीन चंद्र पांडे, धर्मानंद तिवारी को शामिल किया है। राजेंद्र फर्स्टांग ने कहा कि संगठन व्यापारी हितों के साथ-साथ सामाजिक और देवभूमि की संस्कृति मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **एस.एन. राणा** द्वारा आले पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजुड़ चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं कृष्णा लोहा भण्डार, प्रथम तल काला हुंगी रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक: **एस.एन. राणा**
*कार्यकारी सम्पादक **आनन्द बजा 'सुमन'**
☎05946-250286
मुख्यालय: मोवाइल-9720007290 R.N.I. NO. UTHIN/2003/10264 www.shahitimesnews.com email:shahitimes2015@gmail.com
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एवं अंतर्गत उत्तरदायी समस्त विचार मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

गुडवर्क : लक्सर पुलिस ने किया भोगपुर के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा

मंदिर में चोरी का विरोध करने पर की सेवादार की हत्या

शाह टाइम्स संवाददाता
लक्सर। लक्सर कोतवाली पुलिस ने भोगपुर मंदिर के सेवादार ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त हथोड़ा व चुराए गए एम्प्लीफायर क बैटरी भी बरामद कर ली है। पृष्ठताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे की हालत में था और मंदिर में चोरी का प्लान किया था पुजारी के विरोध करने पर उसको हथोड़े से वार कर के मीठ के घाट उतार कर फरार हो गया और अब पुलिस के पकड़े जाने की दर से वह भागने की फिराक में था।



एएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 12 अप्रैल को कोतवाली लक्सर के भोगपुर मंदिर में कार्य करने वाले राजवीर की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस टीम व फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर मौजूद वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए तथा घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान एसपी देहात शंकर चंद्र सुवाल द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। प्रकरण के संबंध में कोतवाली लक्सर पर अज्ञातके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही घटनास्थल के पास ही स्थित अन्य मंदिर से चोरी करने पर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। धार्मिक स्थल पर हत्या व चोरी के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह द्वारा लक्सर के नेतृत्व में गठित

पकड़े जाने के खौफ से शहर छोड़ कर भागने की फिराक में था हत्यारोपी

- ❖ भोगपुर में बुजुर्ग के सिर पर हथोड़ी से वार कर अज्ञात लोगों ने किया था कत्ल
- ❖ हत्या/चोरी में इस्तेमाल हथोड़ा, पेचकश तथा चुराया गया एम्प्लीफायर व इन्वर्टर बरामद
- ❖ आरोपी ने शराब के नशे में दिया था वारदात को अंजाम, अब करेगा हवालात की सैर



बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर हथोड़े से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल किया और फिर पहले मंदिर के अन्दर से चढ़ावे के करीब 200 रूपये और एक इन्वर्टर और फिर बगल वाले मंदिर से एक एम्प्लीफायर चोरी कर ले गया। आरोपी ने ये भी बताया कि वह इसके बाद चोरी किया सामान वही आस-पास छुपाकर वापस चुपचाप अपनी मौसी के घर जा कर सो गया। सुबह जब चारों तरफ पुलिस की गतिविधियां व सतर्कता को देखी तो वह डर के मारे बिना चोरी के सामान के सुबह मुजफ्फरनगर चला गया। कल वह उक्त सामान को लेने के लिए आज टांडा भागलपुर क्षेत्र में आया था जहाँ सामान के साथ पुलिस टीम के हथियार चढ़े हुए।

बेहद कम समय में वास्तविकता को सामने लाकर ब्लाइंड हत्या का खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार करने पर क्षेत्रीय जनता द्वारा एसएसपी नवनीत सिंह व हरिद्वार पुलिस की मेहनती कार्यशैली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। 'विवरण आरोपित-विशाल चौधरी पुत्र परविन्दर कुमार निवासी अलमासपुर गली नं० 02 कुंज विहार कालोनी धाना नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश उम्र 25 वर्ष है। पुलिस टीम-सीओ लक्सर देवेन्द्र सिंह नेगी-प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी- व(उ0)नि0 नितिन चौहान-उ(नि0) शशीवीर सिंह नेगी- हे0 कानि0 रियाज अली-हे0 कानि0 पंचम प्रकाश-हे0कानि0 विनोद कुमार-कानि0 गंगा सिंह-कानि0 ध्वजवीर सिंह-कानि0 वसीम आदि शामिल रहे।

सड़क बनाने में पांच लोगों पर मारपीट का आरोप

शाह टाइम्स संवाददाता
खानपुर। शाहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के पांच लोगों पर सड़क बनाने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शाहपुर गांव निवासी मोनु उर्फ अजय ने तहरीर देकर बताया कि उनके घर के सामने से आम रास्ता होकर जा रहा है। इसपर सीसी रोड बनी हुई है। 13 अप्रैल की सुबह उसके ऊपर इंटरलॉकिंग से दोबारा सड़क बन रही थी लेकिन पड़ोसी उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वह सड़क को दूसरी ओर बनवाना चाहते थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष के पांच लोग लाठी-डंडे, धारदार हथियार और तमंचे से लैस होकर उसके घर पर चढ़ आए व मारपीट कर उसे घायल कर दिया। शोर सुनकर कई लोग मौके पर आ गए थे। उन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। खानपुर थानाध्यक्ष दिग्पाल कोहली ने बताया कि रफाल सिंह, मोनु, रामदेश, शिवा और हर्षित निवासी शाहपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

अवैध शराब सहित दो आरोपी गिरफ्तार

पिरान कलियर। कोतवाली पिरान कलियर पुलिस ने ऑपरेशन 'प्रहार' अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेच रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 113 पब्ले अवैध देशी शराब (माल्टा) बरामद की है। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, असामाजिक तत्वों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने ग्राम मेहवड़कला में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अमित सेनी निवासी मेहवड़ कला और सतीश सेनी निवासी मोहम्मदपुर पांडा को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 113 पब्ले अवैध देशी शराब (माल्टा) बरामद हुई।

बिहार के विशेषज्ञों और महिला उद्यमियों की बड़ी पहल बंजर जलमग्न भूमि पर अब उगेगा सफेद सोना

शाह टाइम्स संवाददाता
लक्सर। उत्तराखंड के कृषि मानचित्र पर एक नया अध्याय खुद शुरू हुआ है। राज्य में कृषि नवाचार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप ने जलभराव वाली चुनौतीपूर्ण भूमि पर मखाना फॉक्स युनिट की खेती का सफल अभिनव प्रयोग शुरू किया है। इस साहसिक पहल का नेतृत्व महिला उद्यमी सोनल जैन एवं मंजू भसीन द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम



में राजीव रंजन अध्यक्ष मणिगाछीमिडास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दरभंगा राजेश शर्मा, अजय पनियुली, रोहताश सहरावत और कर्नल विनोद कुमार पनियुली सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं कृषि विशेषज्ञ उपस्थित थे। चुनौती को अक्सर में बदलापरियोजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि लक्सर क्षेत्र के गंदासपुर गांव में जिस भूमि का चयन किया गया है, वह वर्ष में 5 से 6 महीने जलमग्न रहती थी पारंपरिक फसलों के लिए अनुपयुक्त मानी जाने वाली इस

मौके पर पहुंचकर किसानों और उद्यमियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया। आर्थिक समृद्धि का नया मार्गमखाना खेती उत्तराखंड के किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों के अनुसारलागत और उत्पादन एक बोधा भूमि में मात्र 8.10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है जिससे 4.6 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। बंपर मुनाफा वर्तमान बाजार भाव 800 से 1,200 प्रति किलोग्राम को देखते हुए, किसान प्रति बोधा 2 लाख से 4 लाख तक की संभावित आय अर्जित कर सकते हैं।

मामूली कहासुनी पर युवक को पीटा

शाह टाइम्स संवाददाता
लक्सर। टिककमपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे युवक पर लात-चूसे और बेटों से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर क्षेत्र के टिककमपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर जन्मोत्सव के तहत ग्रामीण शोभायात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान गांव के प्रवीन कुमार और अमन के बीच किसी बात पर हल्की कहासुनी हो गई। शोभायात्रा समाप्त होने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि गुस्साए युवक ने अपने दोस्तों को बुला लिया और घर के बाहर बैठे प्रवीन पर अत्यांक हमला कर दिया। हमलावरों ने प्रवीन को लात-चूसे और बेटों से बेरहमी से पीटा। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े लेकिन ग्रामीणों को आता देख हमलावर फरार

सीएमओ ने आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर की तैयारियों का लिया जायजा

शाह टाइम्स संवाददाता
पिरान कलियर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आर.के. सिंह ने ब्रह्मपतिवार को साबरी गेस्ट हाउस पिरान कलियर में आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रुड़की ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राव अकरम भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉ. आर.के. सिंह ने शिविर के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से मरीजों का परीक्षण और उपचार किया जाएगा। साथ ही सभी प्रकार की खून की जांच, एक्स-रे सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने जानकारी दी कि शिविर में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बहनों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा टीबी और एचआईवी की



जांच की सुविधा भी शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राव अकरम ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं।

बढ़ेड़ी राजपूतान से हलवाहेड़ी तक बनेगी सड़क

शाह टाइम्स संवाददाता
पिरान कलियर। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान अहमद के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के निर्माण की घोषणा की है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी कर ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बढ़ेड़ी राजपूतान से भारापुर होते हुए हलवाहेड़ी तक इस संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विधायक की ओर से मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव भेजा गया था जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति देते हुए निर्माण की घोषणा की है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सड़क बनने के बाद कम दूरी और कम समय में रुड़की सहित अन्य स्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगा। सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि स्थानीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने इस मार्ग को अपनी घोषणा में शामिल किया है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं।

ढंडेरा नप कार्यालय में धरने पर बैठे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि राणा

रुड़की। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं नगर पंचायत ढंडेरा से पूर्व प्रत्याशी रहे रवि राणा मंगलवार को ढंडेरा नगर पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड के गठन के डेढ़ वर्ष बाद भी धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा है। रवि राणा ने कहा कि क्षेत्र को सड़कें बंदहल हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमवाई हुई है। कई स्थानों पर स्टील लाइटें खराब हैं, जबकि अधिकांश जगहों पर लाइटें लगी ही नहीं हैं, जिससे रात में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष और बोर्ड जनसमस्याओं को और ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश नेगी ने पूर्व में भाजपा से बगवत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

शाह टाइम्स संवाददाता
रुड़की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सेविका/मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लंबे समय से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मानदेय बंद कम है, जबकि कार्य का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न मदों में की जा रही कटौती से

कर्मचारियों का आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने के निर्णय को भी उन्होंने अव्यवहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही

नप अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद ने फीता काटकर किया नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास

शाह टाइम्स संवाददाता
पिरान कलियर। नगर पंचायत पिरान कलियर की ओर से बेहतर पानी के लिए थाने के नए धवन के पास एक 260 मीटर नाले का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका शिलान्यास नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद ने फीता काटकर किया।

कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सलीम अहमद और ईओ कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से थाने के नए धवन के पास 25 लाख रूपये की लागत में बनने वाले 260 मीटर नाले के निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने



बताया कि पिरान कलियर में लंबे समय से पानी निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई थी जिसके कारण लोग परेशान थे और बरसात के समय पानी निकासी खोलकर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी और बरसात का पानी लोगों के घरों में भर जाता था जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान उठाने को मजबूर होना पड़ता था पानी निकासी की एक बड़ी समस्या बनी हुई थी जिससे बरसात के समय गंदा पानी घरों में घुसने से किसी भी गम्भीर बीमारी के फैलने की आशंका बनी रहती थी। इस नाले के निर्माण होने से करीब आधे कलियर के पानी की निकासी होगी जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा नगर पंचायत का चहुमुखी विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान, राशिद गुलजार, मौसम, इसरान शरीफ, रोशन, राशिद, शफकत, इतजार राणा, शहाजद, गुलजार चौधरी, तस्वर, हनीफ आदि मौजूद रहे।

माजरा में हज यात्रियों को दिया गया प्रशिक्षण, आसान और सुरक्षित सफर पर जोर

शाह टाइम्स संवाददाता
रुड़की। उत्तराखण्ड से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बुधवार को माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उल्म में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें हाजियों को हज के अरकान अदा करने की जानकारी दी गई।

देहरादून के हज यात्रियों को अध्यक्ष इमाम संगठन मुफ्ती रईस कासिम, मुफ्ती हुजैफा, मौलाना एजाज, राज्य हज समिति सदस्य मौलाना मन्तान रजा और हाजी अबरार ने एहराम, तवाफ, सई सहित हज के विभिन्न अरकान को पूरा करने की प्रक्रिया समझाई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने हाजियों से देश और प्रदेश की तरक्की तथा अमन-चैन के लिए दुआ करने की अपील की। उन्होंने हज यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। उत्तराखण्ड हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने यात्रा को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी हाजियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में किसी भी हाजी को कोई समस्या की सहती है तो राज्य हज इम्पेक्टर से संपर्क कर अपनी समस्या बताएं।



उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी हज यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी अरकान को पूरा करने का आह्वान किया। हज अधिकारी मोहम्मद अहसान ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारीयों साझा कीं। इस दौरान आफताब आलम, मुस्तकीम, स्टेट हज इम्पेक्टर अबुल शाहिद, अब्दुल कादिर, इजहारल हक, मोहम्मद शादाब, गुलशन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

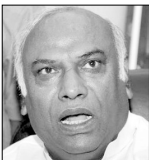
महंगाई की मार

भारत में महंगाई की स्थिति और आम जनमानस पर इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण एक अत्यंत गंभीर और बहुआयामी विषय है। जब हम वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। रोजगार और आय के मोर्चे पर देश की एक बड़ी आबादी के लिए स्थितियां आज भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यह एक विचित्र विरोधाभास है कि एक तरफ सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जाता है कि महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में है और विकास की दरें सकारात्मक हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बढ़ती महंगाई का सीधा और सबसे क्रूर प्रहार आम आदमी को जेब पर पड़ रहा है, जिसे अपने घर चलाने के लिए जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है और कई तरह की मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में जब आय के साधन सीमित हों, तो आम नागरिक की सरकार से यही प्राथमिक अपेक्षा होती है कि कम से कम रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं उसकी पहुंच के भीतर रहें, ताकि परिवार के भरण-पोषण का संकट उत्पन्न न हो, लेकिन हाल के वर्षों का अनुभव यह बताता है कि आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है, जिस गति से बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि फरवरी में यह 3.2 प्रतिशत थी। हालांकि यह आंकड़ा पहली नजर में छोटा लग सकता है, लेकिन जब हम इसके घटकों का बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो वास्तविकता अधिक जटिल नजर आती है। इस महंगाई वृद्धि के पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी एक बड़ा कारक रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों की खुदरा महंगाई पर पड़ता है। विशेष रूप से अमेरिका, इस्पाईल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यदि यह युद्ध की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और अधिक उछाल आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। महंगाई का बढ़ना केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाला कारक है। देश में आर्थिक असंतुलन की खाई और चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ जहां कॉरपोरेट लाभ और उच्च आय वर्ग की संपत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार की कमी और बढ़ती कीमतों ने निम्न और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। जब आय स्थिर हो और क्रय शक्ति घट रही हो, तो आवश्यक वस्तुओं पर होने वाला मामूली सा खर्च भी एक बड़े वित्तीय संकट का रूप ले लेता है।

पुराने संशोधनों को लागू किया जाए

तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लागू करने की योजना बना रही है, वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और जनता को गुमराह करने वाला कदम है, हम सभी महिला आरक्षण बिल को पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से इसे लेकर आई है, वह राजनीति से प्रेरित है, हमने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन हमारा आग्रह है कि पुराने संशोधनों को लागू किया जाए, सरकार परिसीमन और जनगणना के नाम पर चाल चल रही है, कार्यपालिका के जरिए संविधान की उन शक्तियों को हथिया रही है जो संसद और संस्थाओं के पास होनी चाहिए, इन्होंने पहले भी असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन में हमें धोखा दिया है, इसलिए हम इस बिल के मौजूदा स्वरूप का एकजुट होकर संसद में विरोध करेंगे।

—मल्लिकार्जुन खड्गे, अध्यक्ष, कांग्रेस



एक राज्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेते समय, मैंने उस खचाखच भरे कमरे में चारों ओर नजरें घुमाईं और गिनती की। वहां मौजूद महिलाओं की संख्या उगलियों पर गिनी जा सकती थी। इस दृश्य ने केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में ही नहीं, बल्कि इस बात के स्पष्ट संकेत के रूप में भी एक छाप छोड़ी कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।

मैं कनाटक के तटीय इलाके के पुत्रु के पास स्थित एक छोटे से गांव से आती हूँ। पारंपरिक रूप से यह एक समृद्ध इलाका है और यहां की महिलाओं ने हमेशा अपनी दृढ़ता एवं शक्ति का परिचय दिया है। मुझे पता है कि उस शक्ति को सार्वजनिक जीवन में लाने का क्या मतलब होता है। खासकर, उस स्थिति में जब एक ऐसी राह पर चलना हो जिस पर पहले चंद लोग ही चले हों और हर महिला को वैसे ही जोश के साथ वैसा ही मौका नहीं मिला हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है। संसद में सितंबर 2023 में इस पर चर्चा हुई थी और संविधान में संशोधन किया गया था। लेकिन अब उस वादे को निभाने का सबसे मुश्किल काम सामने है।

अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकतंत्र

भारत में कुल 670 मिलियन महिलाएं हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों में महज 15 प्रतिशत महिलाएं ही संसद में पहुंच पाई हैं। जो लोकतंत्र अपने आधे नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से लगभग बाहर रखे, उसे सच्चा लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया में ही माना जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कागज पर लिखे किसी कानून का तभी कोई महत्व होता है, जब उस प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जनगणना करना बेहद जरूरी है। इसके बाद परिसीमन होना चाहिए और संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जब कानून बनाने वाली प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो कानून बनाने का केन्द्रविंदु ही बदल जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में, जहां स्त्रकों पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के पोषण के लिए अधिक बजट आवंटित किए गए। भ्रष्टाचार के प्रति कम सहनशीलता और समुदायों के प्रति

सही समय : महिला आरक्षण से बदलेगी भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर



शोभा कर्ंदलाजे



बयानबाजी भर नहीं, बल्कि एक ऐसा ढ़ विश्वास है जिसने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से लेकर 'जन धन', 'उज्वला' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी वाली नीतियों को दिशा दी है। उन्होंने नारी शक्ति को केवल एक नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत का आधार बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह सोच महिला सशक्तिकरण को कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़ाकर शासन की संरचना में समाहित करती है। सभी दलों के अपने साधियों से यह क्षण हम सभी का है। यह मौका किसी एक दल का नहीं, बल्कि एक संस्था के रूप में संसद का है।

सरकार के हर स्तर पर इस राष्ट्र की सेवा करने वाली एक महिला के रूप में, मैं सभी से अपील करती हूँ और मेरा मानना है कि हम सभी भारत के लोकतंत्र को मजबूत और अधिक पूर्ण देखना चाहते हैं। भारत की महिलाओं के प्रति हमारा अब यह कर्तव्य है कि हम जनगणना कराने, परिसीमन के कार्य को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में तत्परता बरते कि इस प्रक्रिया में एक भी दिन अनावश्यक रूप से बर्बाद न हो। मैं कार्यान्वयन, आरक्षित सीटों के चक्रण (रोटेशन), परीक्षा (प्रॉक्सी) उम्मीदवारों और सनसेट क्लॉज से जुड़ी चिंताओं से अवगत हूँ। यह जायज बहस है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। सिद्धांत सही है। हमें पूर्णता को परिवर्तनकारी कदमों के आड़े नहीं आने देना चाहिए।

(लेखिका केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्यमंत्री हैं)

अधिक जवाबदेही देखी गई। यह महज एक संयोग नहीं है। यह प्रतिनिधित्व का जीता-जागता उदाहरण है।

दुष्कृत को तोड़ना

मैंने अक्सर यह तर्क सुना है कि महिलाओं को अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस भावना का सम्मान करती हूँ। लेकिन इस आधार को खारिज करती हूँ। योग्यता शून्य में नहीं पनपती। यह वहीं पनपती है, जहां अवसर मौजूद होते हैं। पीढ़ियों से, संरचनात्मक बाधाओं-सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक-ने प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति से बाहर रखा है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हमेशा उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास सुस्थापित नेटवर्क एवं संपर्क तथा विरासत में मिली राजनीतिक साख रही है और जो घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। दूसरी ओर, महिलाओं को इनमें से कोई भी सुविधा हासिल नहीं है।

आरक्षण से स्तर कम नहीं होता, बल्कि यह अड़चन को दूर करता है

जब बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायतों में दाखिल हुईं, तो शुरू में उन्हें नजरअंदाज किया गया। आखिरकार, विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि उनके अपने समुदायों ने उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी, अधिक

सुलभ व अधिक ईमानदार माना। जब महिलाओं को उचित अवसर दिया जाता है, तो वे केवल भाग ही नहीं लेती बल्कि नेतृत्व भी करती हैं।

नीतिगत दृष्टि से इसके मायने

सरकार में रहते हुए अपने व्यापक अनुभवों से मैंने यह जाना है कि निर्णय लेने वाले स्थानों पर आपको मौजूदगी ही इस बात को निर्धारित करती है कि किस विषय पर चर्चा होगी। महिला जनप्रतिनिधि मातृ स्वास्थ्य निधि में कटौती की आशंका होने पर इसके लिए आवाज उठाती हैं। वे उन नीतियों के लैंगिक प्रभाव को उजागर करती हैं, जिनका व्यवहार में सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ सकता है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की उन चिंताओं को सामने लाती हैं, जिनसे उनके पुरुष सहकर्मियों का सामना नहीं होता। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मतलब यह है कि पहली बार ए आवाजें अपवाद नहीं रहेंगी। ये आवाजें ढांचागत व्यवस्था का हिस्सा होंगी। स्थाई होंगी। इन्हें नजरअंदाज करना असंभव होगा।

नारी शक्ति : सोच से काबू तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना रहा है कि भारत अपनी निरक्षरताओं की पूर्ण और बराबरी की भागीदारी के बिना अपनी पूरी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर सकता। यह महज एक

पाकिस्तान कब से भारतीय नौकरियों में हस्तक्षेप करके वेतनमान तय करने का परोक्ष-अपरोक्ष अधिकारी बन गया। दरअसल, न्यूज चैनलों ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी गैरत, अपना राष्ट्र धर्म, अपनी भाषा, अपने विषय। सब कुछ पूंजीपतियों व सत्ता के चरणों में न्योछावर कर दिए हैं। 2014 के बाद से एक भी जन सरोकारों के विषयों पर कभी भी चैनलों ने बहस नहीं की। उस पर एकदल विशेष के कार्यकर्ताओं को शो में बुलाकर बेमतलब के टाइमपास विषयों पर बहस, अब एक ट्रेंड बन गया है। जब भी सत्ता पर कोई बात आ रही होती है।

शोषण व चाटुकारिता के भंवर में पत्रकारिता



पवन सिंह

भारत के न्यूज चैनल्स मक्कारी, झूठ और चाटुकारिता से सनी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वह अब सीधे-सीधे राष्ट्र के प्रति युद्ध छेड़ने की परिभाषा में आती है। न्यूज चैनलों ने इस देश के भीतर वह माहौल खड़ा कर दिया है जो कभी भी न तो सीआईए कर पाई और न ही आईएसआई। पूरे देश के सामाजिक ढांचे को न्यूज चैनलों ने तबाह कर दिया है। समुदायों के बीच नफरत की खेती जिस तरह से भारतीय न्यूज चैनलों ने की है, ऐसा आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, न्यायव्यवहारिक, हर एक प्लेटफॉर्म को भारतीय मीडिया ने नष्ट कर दिया है। भारतीय मीडिया ने खुल्लम खुल्ला देश के भीतर एक आतंकवादी जैसा हमला किया, जिसने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बेहद कमजोर कर दिया है। जिस देश में भारतीय न्यूज चैनलों जैसा अस्तित्व हो, वहां किसी भी देश को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नोएडा में हुए श्रमिक असंतोष का ठीकरा

पाकिस्तान के सिर फोड़ना, भारतीय मीडिया के घटिया स्तर को दिखाता है। भारतीय मीडिया 2014 के बाद से जनता के सरोकारों से पूरी तरह से कट चुका है। जो लोग भी न्यूज चैनल्स देखते हैं वह झूठ, मक्कारी, नफरत के जहर को अपने व अपनी पीढ़ियों के भीतर जन्म करते हैं। क्या पाकिस्तान ने भारतीय पूंजीपतियों से कहा था कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जाकर उद्योग लगाओ और श्रमिकों को 10 हजार से 13 हजार का वेतन दो। क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत हो चुकी है कि वह भारत के उद्योगपति को दिशा-निर्देश दे सके। यह कैसी असंवेदनशील पत्रकारिता है कि हमें जिन श्रमिकों के हितों के लिए खड़ा होने की जरूरत थी, हम उनके गुस्से, उनकी लाचारी, उनकी विवशता, उनकी गरीबी, उनके संघर्ष, उनके दर्द, उनकी भूख के साथ न खड़े होकर, सत्ता और पूंजीपतियों के समर्थन में खड़े हो गए। यह सब मिलकर भारत को एक कर्बोलियाई जैसा देश बनाते हैं। जहां समान न्याय और समानता की बात सोचना, रात में सूर्योदय होने जैसा है। लाइट, कैमरा, एक्शन। मैं चहरे पेंट करवाकर, खुद लाखों रुपये का वेतन पैकेज बनाते बाली बाली बाली नाओं को यह एहसास है कि 13 हजार के वेतन में, कैसे जिया जा सकता है? प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 88 प्रतिशत श्रमबल

अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में है। वर्ष, 2022-23 में 57 प्रतिशत स्वरोजगार व 22 प्रतिशत दैनिक श्रमिक हैं, मतलब काम आया न आया टाइम्स। वर्ष, 2020 के आंकड़ों के आधार पर श्रमिकों के कार्यबल को अगर देखें भारत के 476.67 मिलियन श्रमिकों में से 41.19 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में, 26.18 प्रतिशत उद्योग व 32.33 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में करीब 88 प्रतिशत श्रमिक हैं। चलिए अब श्रमिकों पर लिखा ही है तो आपको संविदा कर्मियों को संक्षिप्त सच भी बता ही देते हैं। तथाकथित लोकप्रिय सरकारें व यशस्वी नेता जो साल दर साल अपना वेतन, भत्ते, सुविधाएं। भेज थपथाप कर बढ़ा लेते हैं, वो कभी भी न तो श्रमिकों और न संविदा कर्मियों के दर्द व कर्बोलियाई के लिए सामने आते हैं। वर्ष, 2030 तक संविदा कर्मियों की संख्या करीब 1 करोड़ पार कर जाएगी। विगत 12 वर्षों में, संविदा कर्मचारी क्षेत्र 14-16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। एक अनुमान के अनुसार, राज्य और केंद्रीय सरकारों में कार्यबल का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा संविदा या अनुबंध पर है। वर्ष, 2023 में, 54 लाख संविदा श्रमिक औपचारिक रोजगार में शामिल हुए। क्या पाकिस्तान ने कहा था कि भारत में 13 हजार से 16 हजार वेतनमान पर, नेताओं की प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा खाने-कमाने-लूटने-चूसने का ढांचा खड़ा किया जाए? अगर यह पाकिस्तानी इशारे पर हुआ है तो यह सरकार पर सवालिया निशान लगाया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से हिला कॉरपोरेट तंत्र

कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमगाहट, कांच की ऊंची इमारतों का मोहक आभास और प्रोफेशनलिज्म के बड़े-बड़े दावे यदि इनके भीतर भय, शोषण और दबाव का अंधकार पलता हो, तो यह किसी एक कंपनी की चूक नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी असफलता का संकेत है। अप्रैल 2026 में नासिक स्थित एक आईटी इकाई (टीसीएस) से सामने आया प्रकरण इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहां महिला कर्मियों के सपनों को सुनियोजित ढंग से दबा दिया गया। रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा लेकर आई इन महिलाओं को अपने ही कार्यस्थल पर ऐसे असहनीय दबावों का सामना करना पड़ा, जो किसी भी सभ्य समाज के मूल्यों के सर्वथा विपरीत हैं।

यह मामला केवल यौन शोषण के आरोपों तक सीमित नहीं है इसके भीतर भय, मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक आस्था पर दबाव और अधिकारों के खुले दुरुपयोग की कहीं अधिक गंभीर परतें छिपी हुई हैं। सामने आई शिकायतों के अनुसार, कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने महिला कर्मियों पर अनुचित प्रस्तावों, अश्लील टिप्पणियों और निजी संबंध बनाने के लिए निरंतर दबाव डाला। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें पदोन्नति रोकने, नौकरी समाप्त करने और उनके निजी जीवन को बदनाम करने की धमकियां दी गईं। सत्ता और पद के बल पर किया गया यह आचरण केवल अनैतिकता की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से कानून दंडनीय अपराध है, जो किसी भी

कार्यस्थल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण होना चाहिए। यदि इस घटना से भी ठोस सबक नहीं लिया गया, तो यह महज एक और मामला बनकर रह जाएगा और यह किसी भी समाज की सबसे बड़ी विफलता होगी।



कार्यस्थल की गरिमा, सुरक्षा और विश्वास को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। यह प्रकरण और भयावह तब बनता है, जब स्पष्ट होता है कि यह छिटपुट घटनाएं नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय संगठित तंत्र का परिणाम था। पुलिस जांच और शिकायतों के अनुसार, आठ महिला कर्मचारियों की नौ एफआईआर में सामने आया कि टीम लीडर्स सहित वरिष्ठों ने 2022 से 2026 तक करीब चार वर्षों तक सुनियोजित ढंग से उन्हें निशाना बनाकर दबाव में रखा। पुलिस ने फरवरी से 40 दिन तक महिला पुलिसकर्मियों के जरिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाकर साक्ष्य जुटाए। आरोप हैं कि निजी तस्वीरें-वीडियो से ब्लैकमेल करना, नामाज पढ़ने और गोमांस खाने को मजबूर करना, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और मानसिक रूप से तोड़ना/कुए सब उसी तंत्र के औजार थे। यह स्थिति दिखाती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग संस्थागत रूप ले लेता है, तो पीड़ितों के

लिए आवाज उठाना कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पक्ष मानव संसाधन विभाग की भूमिका पर उठते सवाल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोशा) के तहत हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और समयबद्ध, निष्पक्ष जांच अनिवार्य हैं। इसके बावजूद आरोप हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, ईमेल और लिखित आवेदन दबाए गए, और पीड़ितों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया/यहां तक कि एक एचआर असिस्टेंट जनरल मैनेजर को भी अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिस विभाग पर कर्मचारियों की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी होती है, यदि वही निष्क्रिय या सहभागी दिखे, तो यह कानून की अवहेलना के साथ विश्वास का गंभीर हनन भी है। चा-वर्षों तक लगातार उठती

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई का अभाव यह स्पष्ट करता है कि समस्या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी खामियों में जड़े जमाए हुए थी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोशा) के दिशा-निर्देश स्पष्ट करते हैं कि 24 घंटे के भीतर सजाया लिया जाए और 90 दिनों में जांच पूरी हो, परंतु यहां इन प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की गई। यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। ऐसे मामलों में देरी न केवल पीड़ितों के मानसिक आघात को गहरा करती है, बल्कि आरोपियों के हौसले भी बढ़ाती है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला तब खोखला लगता है, जब सवाल उठता है कि वर्षों तक शिकायतें दबने और पीड़ितों की आवाज अनसुनी रहने के दौरान यह लागू क्यों नहीं हुई। टीसीएस द्वारा उच्च प्रबंधन स्तर पर जांच (सीओओ के निदेशन में) के आदेश और आरोपियों का निलंबन आवश्यक कदम हैं, पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि नेसेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट ने श्रम मंत्रालय से पोशा कंफ्लिक्ट्स ऑडिट की मांग की है। जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे उन सभी स्तरों तक तय होना चाहिए जहां लापरवाही या मिलीभगत रही हो। कॉर्पोरेट संस्थानों की साख मुनाफे या छवि से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान, पारदर्शिता और विश्वास से बनती है। यह घटना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र में कार्यस्थल की सुरक्षा पर गहरे और असहज प्रश्न खड़े करती है। क्या आधुनिक दफ्तर



प्रो. आर.के. जैन

वास्तव में सुरक्षित हैं, या केवल बाहर से सजे-धजे और आकर्षक दिखते हैं? क्या महिलाओं और अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ेगा? यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब तक शिकायत तंत्र मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित और अधूरा ही रहेगा। कर्मचारियों के भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी आवाज न दबेगी, न अनसुनी होगी, बल्कि उसे गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें समयबद्ध न्याय अवश्य मिलेगा। अब समय केवल औपचारिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक सुधार का है। इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच होनी चाहिए, दोषियों को कठोर दंड मिले और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोशा) के अनुपालन की स्वतंत्र ऑडिट पूरे आईटी क्षेत्र में कराई जाए। साथ ही मानव संसाधन तंत्र को स्पष्ट रूप से जवाबदेह बनाया और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

